# Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

**13 अक्टूबर 2026 • हिंदी**

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 13 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

## 1 खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री 2025-26 में रिकॉर्ड ₹1.87 लाख करोड़: सरकारी पृष्ठभूमि नोट

*Khadi and Village Industries Sales Hit Record ₹1.87 Lakh Crore in 2025-26, Says Government Backgrounder*

**SSC • Banking • General**

13 अक्टूबर 2026 को, हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले खादी महोत्सव के दौरान, PIB के एक पृष्ठभूमि नोट में बताया गया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) पारंपरिक हुनर को ग्रामीण उद्यमों में कैसे बदल रहा है। 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री ₹1.87 लाख करोड़ तक पहुंची, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है और 2013-14 की तुलना में 501% अधिक (लगभग छह गुना) है; उत्पादन 380% बढ़कर ₹1,25,296 करोड़ हुआ और इस क्षेत्र में रोज़गार 56% बढ़कर 2.04 करोड़ हो गया। कारीगरों का पारिश्रमिक ₹4 से बढ़कर ₹15 प्रति हैंक हो गया है (एक हैंक यानी 840 गज़ सूत)। लगभग पांच लाख खादी कारीगरों में 80% से अधिक महिलाएं हैं। KVIC के 35 प्रशिक्षण केंद्रों में 2025-26 के दौरान 79,682 लोगों को प्रशिक्षण मिला। मार्च 2008 से KVIC के माध्यम से चल रहे प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से लगभग 97.95 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। नोट में अन्य योजनाओं का भी ज़िक्र है: ग्रामोद्योग विकास योजना, जिसके तहत 3.23 लाख से अधिक मशीनें व टूलकिट बांटे गए; खादी विकास योजना की बाज़ार विकास सहायता; खादी संस्थाओं को 4% की रियायती ब्याज दर पर ऋण; और कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322625

## 2 MoSPI के राज्य सचिव सम्मेलन में पी. के. मिश्रा: मज़बूत सांख्यिकी व्यवस्था एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति

*P. K. Mishra Calls Strong Statistics a Strategic Asset at MoSPI Conference of State Secretaries*

**Banking • SSC • General**

13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा आयोजित राज्यों के योजना, वित्त और IT सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने कहा कि भरोसेमंद आंकड़े अच्छी नीति और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी को केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति माना जाना चाहिए, और देश की माप प्रणालियों को तेज़ी से डिजिटल व औपचारिक होती अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाना होगा। इस दिशा में उन्होंने 2022-23 आधार वर्ष वाली राष्ट्रीय लेखा (National Accounts) की नई शृंखला और संशोधित CPI व IIP शृंखलाओं का उल्लेख किया। उन्होंने ज़ोर दिया कि विकास असल में राज्यों में होता है, राज्य सांख्यिकी कार्यालयों को मज़बूत करने और केंद्र–राज्य समन्वय बेहतर बनाने की ज़रूरत बताई, और कहा कि आगे राष्ट्रीय औसत के साथ राज्य और ज़िला स्तर के आंकड़े भी ज़रूरी होंगे। उन्होंने AI, उपग्रह चित्रों और भू-स्थानिक साधनों के उपयोग का स्वागत किया, पर चेताया कि आंकड़े जल्दी देने के लिए सटीकता या गोपनीयता से समझौता नहीं होना चाहिए।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322662

## 3 नमामि गंगे: गंगा बेसिन में अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का अनुपालन 2017 के 39% से बढ़कर 86%

*Namami Gange: Compliance of Grossly Polluting Industries in Ganga Basin Rises from 39% to 86% Since 2017*

**SSC • General**

जल शक्ति मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2026 को बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत औद्योगिक प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जा रहा है। इसका केंद्र अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (Grossly Polluting Industries, GPI) का वार्षिक निरीक्षण है, जो 2017 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सहयोग से शुरू हुआ। बेसिन के हर GPI की हर साल जांच स्वतंत्र तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ करते हैं — वे अपशिष्ट जल के नमूने लेते हैं, BOD और COD जैसे मानक जांचते हैं, ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था का जुड़ाव परखते हैं और चोरी-छिपे सीधे छोड़े जा रहे अपशिष्ट (बायपास) की तलाश करते हैं। 2025 के चक्र में 3,703 GPI की जांच हुई — गंगा बेसिन में 1,296 और यमुना बेसिन में 2,407 — जो छह राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के 113 ज़िलों में फैले हैं; 2026 के चक्र के लिए 40 संस्थान नामित किए गए हैं। नतीजे: गंगा बेसिन में अनुपालन 2017 के 39% से बढ़कर 2025 में 86% हो गया, और जैविक प्रदूषण (BOD) भार 26 से घटकर लगभग 7.16 टन प्रतिदिन रह गया, यानी करीब 72% की कमी। अब लुगदी व कागज़, चीनी, डिस्टिलरी, कपड़ा और चमड़ा (टैनरी) क्षेत्रों के लिए अलग-अलग चार्टर हैं; पहले के आकलन में ये पांच क्षेत्र कुल GPI का करीब 70% और प्रदूषण भार का 88% थे। 2025 में जांचे गए 41 साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (CETP) में से 27 मानकों पर खरे उतरे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322666

## 4 भारत में पहली बार हुए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फ़ोरम में प्रधानमंत्री ने रखा 'पावर टू एम्पावर' का विचार

*PM Pitches 'Power to Empower' at Bloomberg New Economy Forum, First Edition Held in India*

**Banking • SSC • General**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फ़ोरम को संबोधित किया। कारोबार और नीति जगत के नेताओं की यह वार्षिक बैठक पहली बार भारत में आयोजित हुई है; PIB ने 13 अक्टूबर 2026 को उनके हिंदी भाषण का अंग्रेज़ी रूपांतरण जारी किया। फ़ोरम के विषय, यानी वैश्विक शक्ति के नए स्रोतों, पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि असली सवाल यह नहीं है कि तकनीक, डेटा या ज्ञान किसके पास है, बल्कि यह है कि उसका उपयोग अवसर बढ़ाने के लिए हो रहा है या नहीं; इसी विचार को उन्होंने 'पावर टू एम्पावर' कहा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सस्ता मोबाइल डेटा, रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े शोरूम तक इस्तेमाल होने वाली एक ही डिजिटल भुगतान प्रणाली, JAM त्रिमूर्ति के ज़रिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप का ज़िक्र किया, जिनमें से लगभग आधे छोटे शहरों और कस्बों से हैं। अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बताया कि अप्रैल-जून तिमाही में विकास दर 7.8% रही, पिछले साल चालू खाता घाटा घटकर GDP का 0.61% रह गया और विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से ऊपर है। उन्होंने यह भी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 के लगभग 75 गीगावाट से बढ़कर करीब 300 गीगावाट हो गई है, और भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से 40% बिजली क्षमता का लक्ष्य नवंबर 2021 में ही, तय समय से नौ साल पहले, हासिल कर लिया था।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322622

## 5 NCGG मसूरी में विदेशी सिविल सेवकों के लिए BHASHINI के 'श्रुतलेख' से अंग्रेज़ी-स्पेनिश लाइव अनुवाद

*BHASHINI's Shrutlekh Provides Live English-Spanish Translation for Foreign Civil Servants at NCGG Mussoorie*

**SSC • General**

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारत का भाषा-AI प्लेटफ़ॉर्म BHASHINI मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) द्वारा आयोजित सिविल सेवकों के एक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में रीयल-टाइम अनुवाद उपलब्ध करा रहा है। शहरी सेवा वितरण पर यह कार्यक्रम 12 से 23 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अधीन काम करने वाला NCGG कर रहा है, और इसे भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत विदेश मंत्रालय प्रायोजित कर रहा है। प्रशिक्षु कई देशों से आए हैं, जिनमें पेरू, नाइजीरिया, कंबोडिया, लेबनान और स्पेन शामिल हैं। शुरुआती परिचय सत्र में BHASHINI के 'श्रुतलेख' प्लेटफ़ॉर्म ने अंग्रेज़ी और स्पेनिश के बीच दोनों दिशाओं में बोलचाल का अनुवाद किया, और इसे पूरे कार्यक्रम के दौरान उपलब्ध रखने की योजना है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अधीन डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीज़न द्वारा संचालित BHASHINI को भारत का भाषा संबंधी डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा बताया जाता है। मंत्रालय के अनुसार इसके टूल 800 से अधिक वेबसाइटों सहित 2,353 सरकारी प्लेटफ़ॉर्म में जुड़े हैं, और यह 36 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, 23 भारतीय भाषाओं में आवाज़ और 35 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322621

## 6 भारतीय नौसेना 16 अक्टूबर को कारवार में स्वदेशी मल्टी-पर्पज़ पोत 'समर्थक' को नौसेना में शामिल करेगी

*Indian Navy to Commission Indigenous Multi-Purpose Vessel Samarthak at Karwar on 16 October*

**SSC • General**

रक्षा मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारतीय नौसेना अपना पहला मल्टी-पर्पज़ वेसल (MPV) 'समर्थक' 16 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक के कारवार स्थित नौसेना बेस में नौसेना बेड़े में शामिल करेगी। 'समर्थक' मेक इन इंडिया के तहत लार्सन एंड टुब्रो द्वारा बनाए जा रहे चार MPV में से पहला है, और नौसेना ने इसे युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बताया। यह पोत मुख्य रूप से समुद्री निगरानी और गश्त के लिए है, लेकिन इसे एक लचीले 'यूटिलिटी' मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है: यह कम तीव्रता के समुद्री अभियानों के अलावा लक्ष्य-तैनाती और परीक्षण मंच, मानवरहित व स्वायत्त प्रणालियों के लिए मदर-शिप, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) कार्यों और ज़रूरत पड़ने पर सीमित अस्पताल-पोत में बदले जाने में भी सक्षम है। इसके युद्ध-तंत्र में स्वदेशी सेंसर, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ शामिल हैं। पोत के प्रतीक-चिन्ह में लहरों से निकलता एक भारतीय हाथी दिखाया गया है, जो शक्ति, बुद्धिमत्ता और फुर्ती का प्रतीक है, और इसका आदर्श वाक्य 'विजयार्थम् एकनिष्ठता' है, जिसका अर्थ है 'विजय ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है'।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322795

## 7 BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न, 'दिल्ली घोषणापत्र' स्वीकृत

*First BIMSTEC Home Ministers' Meeting Concludes in New Delhi with Adoption of the Delhi Declaration*

**SSC • General**

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भारत द्वारा आयोजित BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई और उसी दिन सातों BIMSTEC सदस्य देशों - बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड - के गृह मंत्रियों ने 'दिल्ली घोषणापत्र' स्वीकार कर बैठक का समापन किया। घोषणापत्र के अनुसार इस तंत्र की नींव काठमांडू में हुए चौथे BIMSTEC शिखर सम्मेलन (अगस्त 2018) में पड़ी थी, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठकों के साथ-साथ गृह मंत्रियों की बैठकों का प्रस्ताव रखा गया था, और बैंकॉक में हुए छठे शिखर सम्मेलन (अप्रैल 2025) में इसे औपचारिक मंज़ूरी मिली। घोषणापत्र में मंत्रियों ने आतंकवाद और सीमापार आतंकवाद को 'हर रूप में' कड़ी निंदा की, मार्च 2021 से प्रभावी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध व नशीली दवाओं की तस्करी रोकने संबंधी BIMSTEC अभिसमय और मार्च 2022 में हस्ताक्षरित आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी अभिसमय को पूरी तरह लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई, और प्रत्यर्पण, दंडित व्यक्तियों के स्थानांतरण तथा मानव तस्करी-रोधी मसौदा अभिसमयों को जल्द अंतिम रूप देने की अपील की। उन्होंने तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग पर भी चिंता जताई, जिसके ज़रिए संगठित अपराध गिरोह तस्करी के शिकार लोगों को ऑनलाइन स्कैम गिरोहों में काम करने को मजबूर कर रहे हैं, और नियमित रूप से ऐसी बैठकें करते रहने का संकल्प लिया।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322964

## 8 EPFO: PF ट्रस्टों की छूट-स्थिति नियमित करने की माफी योजना की समय-सीमा 28 दिसंबर नज़दीक, जागरूकता अभियान तेज़

*EPFO Steps Up Outreach as Amnesty Window for PF Trusts' Exemption Status Nears 28 December Deadline*

**Banking • SSC • General**

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 13 अक्टूबर 2026 को देशभर में अपना जागरूकता अभियान तेज़ कर दिया, क्योंकि भविष्य निधि (PF) ट्रस्टों के लिए छूट-स्थिति नियमित कराने की छह महीने की 'माफी' (Amnesty) खिड़की की 28 दिसंबर 2026 की समय-सीमा नज़दीक आ रही है। यह माफी प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 (29 जून 2026 को अधिसूचित) के तहत लाया गया, और इसके परिचालन दिशा-निर्देश 11 जुलाई 2026 को जारी हुए। यह उन PF ट्रस्टों को एक बार का मौका देता है जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पहले से मान्यता-प्राप्त हैं, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 के तहत औपचारिक छूट आदेश नहीं रखते - ऐसे ट्रस्ट अब पूर्वव्यापी रूप से अपनी छूट-स्थिति नियमित करा सकते हैं। नियमितीकरण के अलावा, यह योजना सामाजिक सुरक्षा संहिता की कुछ शर्तों - जैसे न्यूनतम कर्मचारी संख्या, न्यूनतम कोष आकार और तीन साल के अनुपालन नियम - में छूट देती है, और नियमित हो चुके ट्रस्ट को आगे छूट-प्राप्त या गैर-छूट-प्राप्त संस्था के रूप में काम करने की पूरी छूट देती है। EPFO ने CII, ICAI और BSE जैसी संस्थाओं के साथ सेमिनार आयोजित किए हैं, पात्र ट्रस्टों की पहचान के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट व सांविधिक लेखा-परीक्षकों को शामिल किया है, अपने फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, और शेष अनियमित ट्रस्टों का पता लगाने के लिए आयकर विभाग के रिकॉर्ड से मिलान कर रहा है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322732

## 9 भारतीय रेलवे की सितंबर 2026 में माल ढुलाई में 6.14% वृद्धि, खाद्यान्न और क्लिंकर में सबसे तेज़ बढ़त

*Indian Railways Posts 6.14% Rise in Freight Loading in September 2026, Led by Food Grain and Clinker*

**Banking • SSC • General**

रेल मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारतीय रेलवे ने सितंबर 2026 में 135.35 मिलियन टन माल ढोया, जो सितंबर 2025 के 127.52 मिलियन टन से 6.14% अधिक है। प्रमुख वस्तुओं में खाद्यान्न की ढुलाई सबसे तेज़, 25%, बढ़ी, इसके बाद क्लिंकर (20%), घरेलू कंटेनर (10%), कोयला (9%), अन्य सामान (8.2%), खनिज तेल (6%), तैयार इस्पात (5.5%) और लौह अयस्क (5.2%) का स्थान रहा। रेलवे ने बिजलीघरों को कोयला आपूर्ति भी बढ़ाई - सितंबर 2026 में औसतन रोज़ाना 443 रेक भेजे गए, जबकि एक साल पहले यह संख्या 397 थी, यानी 11.6% की वृद्धि। माल भाड़े से होने वाली आय सितंबर 2025 की तुलना में ₹1,266 करोड़ बढ़ी, यानी 9.3% की वृद्धि। 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में संचयी माल ढुलाई 833.7 मिलियन टन के पार पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 4.1% अधिक है, जबकि माल भाड़ा आय में 3.7% की वृद्धि दर्ज हुई।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322673

## 10 मुंबई में समुद्री राज्य विकास परिषद की 21वीं बैठक: 'मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030' के लक्ष्य स्वीकृत, पोत-निर्माण के लिए नई बीमा योजनाएं

*21st Maritime State Development Council Meets in Mumbai, Adopts Maritime India Vision 2030 and New Shipbuilding Insurance Covers*

**Banking • SSC • General**

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की 21वीं बैठक 13 अक्टूबर 2026 को मुंबई में संपन्न हुई। भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (15 मई 2026 को अधिसूचित) के तहत सांविधिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में मान्यता मिलने के बाद परिषद की यह पहली बैठक थी; MSDC की स्थापना मूल रूप से 1997 में केंद्र और तटीय राज्यों के बीच समन्वय के एक गैर-सांविधिक मंच के रूप में हुई थी। बैठक में तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री, प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष और संबद्ध समुद्री संस्थाओं के प्रमुख शामिल हुए। परिषद ने 'मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030' और 'मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047' के लक्ष्यों को स्वीकृति दी, और तय किया कि 'वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस' (ONOP) सुधार - जिसमें साझा दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रिया पुनर्रचना शामिल है - मार्च 2027 तक सभी बंदरगाहों पर लागू हों, और सभी बंदरगाह 'मैरीटाइम सिंगल विंडो' (सागर सेतु) से जुड़ जाएं। मंत्री सोनोवाल ने पोत-निर्माण क्षेत्र के लिए दो नई ऋण-जोखिम बीमा योजनाएं भी शुरू कीं - निर्यात परियोजनाओं के लिए ECGC की 'शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी' (SbPCP) और घरेलू परियोजनाओं के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस की 'बिज़नेस क्रेडिट शील्ड पॉलिसी-शिपबिल्डर्स' (BCSPS) - जिनका मकसद लंबी पोत-निर्माण परियोजनाओं के दौरान भुगतान में देरी और जोखिम से शिपयार्ड को बचाना है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322942

## 11 PIB पृष्ठभूमि नोट: भारत में TB के मामले 2015-2024 के बीच 21% घटे, वैश्विक गिरावट सिर्फ 12%; युवाओं के लिए 'JOSH' अभियान शुरू

*PIB Backgrounder: India's TB Cases Fall 21% (2015-2024) Against 12% Global Decline, JOSH Youth Campaign Launched*

**SSC • General**

13 अक्टूबर 2026 को जारी PIB के एक पृष्ठभूमि नोट में WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के हवाले से भारत की टीबी-रोधी प्रगति बताई गई: 2015 से 2024 के बीच भारत में हर साल सामने आने वाले नए टीबी मामलों में 21% की कमी आई, जबकि वैश्विक स्तर पर यह गिरावट केवल 12% रही; इसी अवधि में टीबी से होने वाली मौतें 28% घटीं, और भारत का उपचार कवरेज 92% है जबकि वैश्विक औसत 78% है। सघन 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के तहत अब तक 28.1 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, 20 लाख लोगों को टीबी निवारक उपचार (TPT) दिया गया है, और 5.7 लाख नए 'निक्षय मित्र' (मरीजों की मदद करने वाले स्वयंसेवी 'टीबी मित्र') जुड़े हैं; अभियान के तहत उपचार सफलता दर बढ़कर 90% हो गई है, जो 88% के वैश्विक औसत से अधिक है। नोट में 13 अक्टूबर 2026 को शुरू हुए 'JOSH' (जॉइंट स्क्वॉड फॉर हेल्थ) अभियान की भी घोषणा की गई, जो फिलहाल 11 राज्यों के 55 ज़िलों में पायलट आधार पर चलेगा; इसमें 'MY भारत' के स्वयंसेवकों और NCC कैडेटों की टीमें, एक प्रथम श्रेणी अधिकारी के नेतृत्व में, स्क्रीनिंग और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाएंगी। हाल के अन्य कदमों में दवा-प्रतिरोधी टीबी के लिए छह महीने का छोटा BPaLM उपचार (अब तक 15,000 से अधिक मरीज़ों को दिया गया) और हैंडहेल्ड AI-सक्षम उपकरणों से एक्स-रे स्क्रीनिंग में 34 गुना वृद्धि शामिल है। 13 अक्टूबर 2026 तक देश में 1,87,250 आयुष्मान आरोग्य मंदिर टीबी की जांच की सुविधा दे रहे हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322820

## 12 ICAR का सोयाबीन हार्वेस्ट डे: प्रतिकूल मौसम के बावजूद नई किस्में NRC 268 और NRC 270 में लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज के संकेत

*ICAR's Soybean Harvest Day: New Varieties NRC 268 and NRC 270 Show Yields Near 20 Quintals/Hectare Despite Poor Weather*

**SSC • General**

कृषि मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2026 को बताया कि ICAR-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर ने 9 अक्टूबर 2026 को 'सोयाबीन हार्वेस्ट डे' आयोजित कर अपनी विकसित दो उन्नत किस्मों - NRC 268 और NRC 270 - की उपज क्षमता का आकलन किया। दोनों किस्मों के एक-एक एकड़ में कटाई से मिले शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, इस साल की प्रतिकूल मौसम स्थितियों के बावजूद लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिली, जो भारत की मौजूदा औसत सोयाबीन उत्पादकता (लगभग 10-11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) से काफी अधिक है। संस्थान और अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के तहत हुए परीक्षणों के अनुसार, उन्नत किस्मों और उचित उत्पादन तकनीकों से आम तौर पर 15-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और अनुकूल परिस्थितियों में 22-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज संभव है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट ने कहा कि मुश्किल मौसम वर्ष के बावजूद मिले ये नतीजे उत्साहजनक हैं, और ऐसे आयोजनों से मिलने वाला बहु-वर्षीय व्यवस्थित आंकड़ा देश में सोयाबीन उत्पादकता बढ़ाने की भावी शोध रणनीति तय करने में मदद करेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322744

## 13 खान मंत्रालय ने अंडमान सागर के दो अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया

*Mines Ministry Holds Outreach Programme for Auction of Two Offshore Mineral Blocks in the Andaman Sea*

**Banking • SSC • General**

खान मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में अपतटीय खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी से पहले संभावित बोलीदाताओं के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। 1 अक्टूबर 2026 की निविदा सूचना (NIT) के तहत अंडमान सागर में स्थित दो ब्लॉक - सेवेल राइज़-01 (632 वर्ग किलोमीटर) और वेस्ट सेवेल रिज-01 (1,000 वर्ग किलोमीटर), कुल मिलाकर 1,632 वर्ग किलोमीटर - पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स व क्रस्ट (जिनमें निकेल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज़ जैसे खनिज होते हैं) के लिए कम्पोज़िट लाइसेंस के तहत नीलाम किए जा रहे हैं। यह नीलामी अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) और अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के तहत हो रही है। कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने ब्लॉकों की भूवैज्ञानिक जानकारी दी, लेन-देन सलाहकार SBI कैपिटल मार्केट्स ने बोली प्रक्रिया समझाई, और नीलामी मंच संचालक MSTC ने ई-नीलामी पोर्टल का प्रदर्शन किया; राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास न्यास (NMEDT) ने भावी कम्पोज़िट लाइसेंसधारकों के अन्वेषण खर्च की आंशिक प्रतिपूर्ति की योजना की जानकारी दी। घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्री-बिड कॉन्फ्रेंस 4 नवंबर 2026 को होगी और बोली जमा करने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322967

## आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

**प्र.1** सुबिक खाड़ी में ADMM-Plus JCA में भाग लेने वाला आईएनएस सह्याद्रि किस श्रेणी का युद्धपोत है?

(A) कोरा-श्रेणी कार्वेट
(B) शिवालिक-श्रेणी फ्रिगेट
(C) तलवार-श्रेणी फ्रिगेट
(D) कोलकाता-श्रेणी विध्वंसक

**प्र.2** दूरसंचार विभाग (DoT) की सितंबर 2026 की सलाह के अनुसार, फर्जी सिम जारी करने और IMEI से छेड़छाड़ पर किस अधिनियम के तहत 3 वर्ष तक की कैद और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है?

(A) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
(B) भारतीय तार अधिनियम, 1885
(C) दूरसंचार अधिनियम, 2023
(D) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

**प्र.3** युवाओं के लिए विज्ञान-आधारित प्रश्नोत्तरी 'CSIR SciQuiz' किस सरकारी युवा-सहभागिता मंच पर आयोजित की जा रही है?

(A) डिजिटल इंडिया पोर्टल
(B) माय भारत (मेरा युवा भारत)
(C) राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल
(D) स्किल इंडिया डिजिटल

**प्र.4** 'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर' तटीय-सफाई अभियान का नेतृत्व, इसकी पृथ्वी (PRITHVI) योजना के अंतर्गत, कौन सा मंत्रालय करता है?

(A) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(B) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
(C) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
(D) गृह मंत्रालय

**प्र.5** लगभग ₹9,805 करोड़ मूल्य का नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल (NGMV) कार्यक्रम अनुबंध रक्षा मंत्रालय के साथ किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था?

(A) 2021
(B) 2022
(C) 2023
(D) 2024

**उत्तर: 1-(B) 2-(C) 3-(B) 4-(B) 5-(C)**

**रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/**
वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)
ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। लेखक/संपादक: Mahesh Srivastava, Founder.